नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 01
दि. 01.10.2025,
बुधवार
पाना : 4
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

खबर संक्षेप

पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा धमाका: एफसी मुख्यालय के पास हमला, 10 की मौत

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा मंगलवार को एक जोरदार धमाके से दहल उठी। यह हमला फ्रंटियर कांस्टेबुलरी (एफसी) मुख्यालय के पास हुआ, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 19 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि धमाका विशेष रूप से सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किया गया था।

धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और कई दुकानों की खिड़कियां टूट गईं। इस घटना के तुरंत बाद मौके पर भगदड़ मच गई। सोशल मीडिया पर सामने आए सीसीटीवी फुटेज में धमाके के समय की भयावह स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।

बलूचिस्तान स्वास्थ्य विभाग ने घटना के तुरंत बाद शहर के सभी अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया। प्रांतीय स्वास्थ्य सचिव मुजीबुर रहमान ने सभी डॉक्टरों, कंसल्टेंट्स, फार्मासिस्ट, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को तुरंत ड्यूटी पर उपस्थित रहने का आदेश दिया। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता डॉ. वसीम बैग ने बताया कि घायलों को सिविल अस्पताल के आकस्मिक और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। कई घायलों की हालत गंभीर होने के कारण मृतकों की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है।

यह हमला बलूचिस्तान में सुरक्षा स्थिति की चिंता बढ़ाने वाला है और स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं।

आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर लगाया 32 लाख रुपये का जुर्माना

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) पर 31.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना बैंक द्वारा 'प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) – लक्ष्य और वर्गीकरण' से संबंधित आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया है।

आरबीआई के अनुसार, बैंक ने कुछ पीएसएल खातों में ऋण-संबंधी शुल्क वसूले, जबकि प्रत्येक ऋण की सीमा 25,000 रुपये तक थी। बैंक को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके जवाब और अतिरिक्त प्रस्तुतियों की समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की गई। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना केवल नियामक अनुपालन में कमी के आधार पर लगाया गया है और इसका उद्देश्य बैंक के ग्राहकों के साथ किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है। इस कदम का मकसद बैंकिंग संस्थानों में नियमों के पालन को सुनिश्चित करना और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लक्ष्यों के प्रति अनुशासन बनाए रखना है।

अविनाश कुमार झारखंड के नए मुख्य सचिव बने

रांची। झारखंड सरकार ने 1993 बैच के आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। प्रशासनिक विशेषज्ञता और तेज़ तर्रार शैली के लिए जाने जाने वाले अविनाश कुमार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1993 में चयन के बाद संयुक्त बिहार के भोजपुर जिले से अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत की।

उन्होंने भोजपुर में एसडीओ, पश्चिमी सिंहभूम में डीडीसी और बेगुसराय, देवघर व लखीसराय जिलों में डीसी के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। झारखंड के निर्माण के बाद उन्हें देवघर का डीसी नियुक्त किया गया और बाद में दुमका व रांची में भी डीसी के रूप में काम किया।

अविनाश कुमार झारखंड में कई अहम विभागों में तैनात रहे हैं। हाल तक वे ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के प्रभार में कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति से राज्य प्रशासन में अनुभव और नेतृत्व क्षमता का और सशक्तिकरण होने की उम्मीद जताई जा रही है।

प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ने की संभावना, दाखिले का दौर शुरू

जमशेदपुर। निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए इस साल भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिकांश स्कूल ऑनलाइन फॉर्म वितरण करेंगे, जबकि कुछ स्कूलों में ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। शहर के लगभग 60 निजी स्कूल प्रवेश कक्षा के लिए फॉर्म वितरण के माध्यम से नामांकन की प्रक्रिया करते हैं। इन स्कूलों में लाटरी प्रणाली के जरिए चयनित बच्चों की सूची तैयार की जाती है। कई स्कूलों में आवेदन प्रक्रिया सितंबर महीने से शुरू हो चुकी है, जबकि कुछ स्कूल अक्टूबर से फॉर्म वितरण का कार्य शुरू करेंगे। इस दौरान प्राइवेट स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है, जिसे स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच चर्चाओं के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट: देश में अपराध का बढ़ता ग्राफ, आत्महत्याओं और साइबर अपराधों ने बढ़ाई चिंता

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें साफ़ दिखता है कि देश में अपराध और आत्महत्या के मामलों की स्थिति बेहद चिंताजनक होती जा रही है। रिपोर्ट के आंकड़े केवल अपराध की गंभीरता ही नहीं बताते, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि समाज के भीतर तनाव, असमानता और नई तकनीकों के दुरुपयोग ने अपराध के स्वरूप को और खतरनाक बना दिया है।

सबसे पहले हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की बात करें तो रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2023 में हर घंटे औसतन तीन घटनाएं दर्ज हुईं। वर्ष भर में हत्या के 27,222 मामले सामने आए, जो 2022 की तुलना में थोड़े कम हैं, लेकिन अभी भी बहुत अधिक हैं। विवाद, दुश्मनी और बदले की भावना इन हत्याओं की बड़ी वजह बताई गई है। बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं। 2023 में महिलाओं से जुड़े अपराधों के 4,48,211 मामले दर्ज किए गए, जिनमें पति और परिवार से जुड़े मामलों की संख्या सबसे अधिक रही। अपहरण, दहेज हत्या और पॉक्सो कानून के तहत दर्ज मामले भी काफी चिंताजनक हैं।

रिपोर्ट में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों में 28.8% की वृद्धि का विशेष उल्लेख किया गया है। 2022 में ऐसे 10,064 मामले सामने आए थे, जबकि 2023 में यह संख्या बढ़कर 12,960 हो गई। यह आँकड़ा इस बात की ओर इशारा करता है कि सामाजिक असमानता और जातीय भेदभाव की जड़ें अभी भी गहरी हैं।

साइबर अपराधों की स्थिति और भी भयावह है। 2022 की तुलना में 2023 में साइबर अपराधों में 31% की वृद्धि हुई और कुल 86,420 मामले दर्ज किए गए। इनमें से करीब 69% मामले ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़े थे। यौन शोषण और जबरन वसूली के भी हजारों मामले सामने आए। यह बताता है कि डिजिटल दुनिया के विस्तार के साथ अपराधी तकनीक का दुरुपयोग कर रहे हैं और आम लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं।

देश में आत्महत्या की घटनाओं ने भी बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। 2023 में कुल 1,71,418 लोगों ने अपनी जान दी। पारिवारिक समस्याएँ (31.9%) और बीमारियाँ (19%) इन आत्महत्याओं की सबसे बड़ी वजह रहीं। छात्रों और बेरोजगारों की आत्महत्या भी चौंकाने वाली है, जहाँ 13,892 युवाओं ने हताश होकर जीवन समाप्त कर लिया। परीक्षा में असफल होने के बाद 1303 छात्रों ने आत्महत्या की। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य रहे, जहाँ आत्महत्या की घटनाएँ सबसे अधिक दर्ज की गईं। किसानों और मजदूरों की आत्महत्या का विषय इस रिपोर्ट का सबसे दुखद हिस्सा है। 2023 में 10,700 से अधिक कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें से ज़्यादातर खेतिहर मज़दूर थे। महाराष्ट्र और कर्नाटक इस त्रासदी के सबसे बड़े केंद्र बने। यह आंकड़ा खेती-किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदहाल स्थिति को दर्शाता है।

रिपोर्ट में बच्चों के खिलाफ अपराध और किशोर अपराध (जुवेनाइल क्राइम) पर भी रोशनी डाली गई है। 2023 में बच्चों के खिलाफ 1,77,335 मामले दर्ज हुए, जो पिछले वर्ष से 9% अधिक हैं। वहीं किशोरों द्वारा किए गए अपराधों की दर 7.1% तक पहुँच गई। अपहरण-बंधक के 1.16 लाख मामले भी दर्ज हुए, जिनमें शादी के लिए अपहरण और बच्चों के भाग जाने से जुड़े मामले प्रमुख रहे।

विदेशी नागरिक भी अपराध के शिकार बने। 2023 में विदेशियों के खिलाफ अपराधों के 238 मामले दर्ज हुए, जिनमें से सबसे ज़्यादा दिल्ली में सामने आए। चोरी और बलात्कार इनमें प्रमुख अपराध रहे। वहीं, विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में किए गए अपराधों की संख्या भी 21% बढ़ गई।

यह पूरी रिपोर्ट बताती है कि देश में अपराध केवल संख्या का खेल नहीं रह गया है, बल्कि यह समाज की जड़ों को कमजोर करने वाला एक गहरा संकट है। हत्या, बलात्कार, आत्महत्या, साइबर अपराध, किसानों की मौत और महिलाओं व बच्चों के खिलाफ बढ़ते मामले यह संदेश देते हैं कि केवल कानून बनाने से स्थिति नहीं सुधरेगी। इसके लिए सामाजिक सुधार, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान, तकनीकी सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना ज़रूरी है।

करूर त्रासदी पर विजय का भावुक संदेश: पीड़ितों के परिजनों से मिलेंगे, बोले- दिल दर्द से भरा

तमिलनाडु के करूर में एक्टर और नेता विजय की राजनीतिक रैली में हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत के तीन दिन बाद, विजय ने मंगलवार को अपना पहला वीडियो संदेश जारी किया। इस संदेश में उन्होंने त्रासदी पर दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों से मिलने का वादा किया।

विजय ने अपने संदेश में कहा, ₹मेरा दिल बस दर्द से भरा है। लोग इस दौरे पर हमें देखने क्यों आते हैं? केवल उनके प्यार और स्नेह के कारण। मैं हमेशा उनके इस प्रेम का ऋणी रहा हूँ।₹ उन्होंने यह भी बताया कि इस दौरे में उन्होंने लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा और इसके लिए उचित स्थानों का चयन किया तथा अनुमति ली।

अभिनेता-नेता ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक कारणों को दरकिनार कर सिर्फ़ जनता की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया, और इस त्रासदी में शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि उनकी पार्टी के पदाधिकारियों को कोई नुकसान न पहुँचाया जाए। विजय ने स्पष्ट किया कि उनके घर या कार्यालय में आकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन उनके पदाधिकारियों के खिलाफ नहीं।

विजय ने अंत में यह भरोसा भी दिलाया कि जल्द ही घटना का पूरा सच सामने आएगा और उन्होंने पीड़ित परिवारों से मिलने का अपना वादा दोहराया। उनका यह भावुक संदेश करूर त्रासदी के बाद सामाजिक और राजनीतिक विवादों के बीच लोगों के दिलों में संवेदना और सहानुभूति जगाने की कोशिश माना जा रहा है।

सट्टेबाज़ी जांच में नया मोड़: उर्वशी रौतेला ईडी दफ्तर पहुंचीं

अभिनेत्री और मॉडल उर्वशी रौतेला मंगलवार को '1एक्स बीईटी' नामक ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुईं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, उर्वशी रौतेला इस प्लेटफॉर्म की भारत में ब्रांड एंबेसडर हैं। यह प्लेटफॉर्म कैरेबियाई द्वीप कुराकाओ में पंजीकृत है।

सूत्रों ने बताया कि ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में ईडी ने इस मामले में कई अन्य नामचीन हस्तियों से भी पूछताछ की है, जिनमें क्रिकेटर युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा, शिखर धवन, अभिनेता सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती (पूर्व टीएमसी सांसद) और बंगाली सिनेमा कलाकार अंकुश हाजरा शामिल हैं। इसके अलावा, कुछ चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से भी एजेंसी ने पूछताछ की है।

जांच में पाया गया कि 1एक्सबीईटी से जुड़े कुछ हस्तियों ने प्लेटफॉर्म से प्राप्त विज्ञापन शुल्क का इस्तेमाल विभिन्न संपत्तियों की खरीद में किया। ये संपत्तियां धन शोधन विरोधी कानून के तहत ₹अपराध की आय₹ के रूप में दर्ज की गई हैं। एजेंसी द्वारा इन खिलाड़ियों और अभिनेताओं की करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त करने की संभावना भी बताई जा रही है।

1एक्सबीईटी प्लेटफॉर्म अपने 18 वर्षों के अनुभव के साथ सट्टेबाजी उद्योग में सक्रिय है। इसकी वेबसाइट और मोबाइल ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध है, और उपयोगकर्ता हजारों खेल आयोजनों पर दांव लगा सकते हैं।

हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत में वास्तविक धन वाले ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया है। सरकारी प्रतिबंध से पहले किए गए अनुमानों के अनुसार, ऐसे ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के लगभग 22 करोड़ भारतीय उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से करीब आधे नियमित रूप से इन्हें इस्तेमाल करते हैं। यह मामला अब तक की सबसे बड़ी हस्तियों से जुड़ी सट्टेबाजी जांच में से एक बन चुका है और इसमें शामिल नामचीन हस्तियों की संपत्ति और वित्तीय लेन-देन की गहन जांच जारी है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का निधन, राजनीति में छोड़ी अमिट छाप

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ और प्रगतिशील नेता विजय कुमार मल्होत्रा का मंगलवार को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के AIIMS में उपचाराधीन थे, जहां सुबह उनका निधन हुआ। विजय कुमार मल्होत्रा ने दिल्ली की राजनीति में लंबा और प्रभावशाली करियर बिताया। वे दिल्ली से पाँच बार सांसद और दो बार विधायक रहे। पार्टी के लिए उनका योगदान अतुलनीय रहा। 1980 में उन्होंने दिल्ली भाजपा के पहले प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला। इसके अलावा, 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दक्षिण दिल्ली से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हराकर राजनीतिक महत्व को और भी बढ़ा दिया था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विजय कुमार मल्होत्रा के पार्थिव शरीर को दिल्ली स्थित उनके आवास पर रखा गया है, जहां पार्टी नेताओं और समर्थकों ने उन्हें अंतिम विदाई दी।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर जोर: नायडू ने सीतारमण से पूर्वोदय योजना के लिए मांगा विशेष फंड

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और राज्य के विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता की मांग की। उन्होंने विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए पूर्वोदय योजना के तहत आंध्र प्रदेश को लक्षित फंड देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्वोदय योजना के तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को पहले ही लाभार्थियों के रूप में चिन्हित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य पूर्वी राज्यों के कृषि, औद्योगिक और बुनियादी ढाँचे के विकास के माध्यम से आर्थिक क्षमता को उजागर करना और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है।

नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने योजना के धन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीतियाँ तैयार की हैं। उन्होंने वित्त मंत्री को बताया कि राज्य में रायलसीमा में बागवानी को बढ़ावा देना, उत्तरी आंध्र में कॉफ़ी, काजू और नारियल के बागानों का विस्तार करना तथा तटीय क्षेत्रों में जलीय कृषि गतिविधियों को मजबूत करना प्रमुख लक्ष्य हैं। इसके माध्यम से न केवल उत्पादकता में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के अवसर भी बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से यह रेखांकित किया कि पूर्वोदय योजना का कार्यान्वयन उत्तरी आंध्र और रायलसीमा जैसे पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक और औद्योगिक उत्थान में बदलाव लाएगा, जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे हैं। इस बैठक के अलावा, नायडू सीआईआई के कर्टेन-रेजर साझेदारी शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे, जहाँ वे निवेशकों को राज्य में निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी देंगे और नवंबर में विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाले सीआईआई शिखर सम्मेलन में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे।

संपादकीय

पानीपत जैसी घटनाएं बर्दाश्त न की जाएं

निश्चय ही पानीपत की वह घटना किसी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है, जिसमें एक सात साल के बच्चे को उसके शिक्षक ने सबक सिखाने के लिये कक्षा में उलटा लटका दिया। वाकई यह एक शर्मनाक घटना है, जिसका मानसिक आघात बच्चे के मन पर जीवनपर्यंत बना रह सकता है। यह घटना शहरी इलाके में घटित हुई है लेकिन देश के ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में ऐसे वाकये अपवाद नहीं हैं। गाहे-बगाहे ऐसी घटनाएं अखबारों की सुर्खियां बनती रहती हैं, जिसमें शिक्षक क्रूरता की हदें पार करते नजर आते हैं। विगत के दशकों में बच्चों के साथ स्कूलों में निर्मम व्यवहार एक परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा रहा है। बताते हैं कि पानीपत की परेशान करने वाली घटना का कारण छात्र द्वारा कथित तौर पर होमवर्क न करना रहा है। जिसके चलते इस छात्र को यह अमानवीय सजा दी गई। एक वायरल हुए वीडियो में देखा जा रहा है कि यह बच्चा असहाय और सहमा लटका नजर आ रहा था। कक्षा के अन्य डरे सहपाठी उसे देख रहे थे। अंदाजा लगाना कठिन नहीं है कि इस घटना से बच्चे के मन-मस्तिष्क पर कितना बड़ा आघात पहुंचा होगा। जिससे शायद ही जीवनभर वह मुक्त हो पाए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद समाज के विभिन्न वर्गों में व्यापक आक्रोश देखा गया। हालांकि, यह घटना बीते अगस्त माह की बतायी जा रही है, लेकिन इसका वीडियो देर से पिछले दिनों सामने आया। जिसको लेकर समाज में तल्ख प्रतिक्रिया देखी जा रही है। इसे वाकये को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि स्कूल प्रशासन ने मामले को क्यों दबाया? क्या स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी? वहीं दूसरी ओर सवाल यह भी उठाये जा रहे हैं कि अभिभावकों ने इस घटना के बाबत समय रहते शिकायत क्यों नहीं की? निश्चय ही ऐसे सभी सवालों के जवाब सामने आने चाहिए। विडंबना यह है कि यह सिर्फ पानीपत की ही अकेली घटना नहीं है। सिर्फ सितंबर में ही देश के विभिन्न भागों से स्तब्ध करने वाली कई घटनाएं सामने आई हैं। ऐसी ही एक परेशान करने वाली घटना छत्तीसगढ़ में प्रकाश में आई है। जहां एक लड़की को सौ बार उठक-बैठक करने पर मजबूर किया गया। उसे तब तक पीटा गया जब तक वह चलने लायक रही। एक विचलित करने वाली घटना में नागपुर में कचरा साफ करने से इनकार करने पर कक्षा पांच की दो छात्राओं को डंडे से पीटा गया। इसी तरह विशाखापत्तनम में एक प्रधानाचार्य ने दो किशोरों को लोहे के स्केल से पीट कर प्रताड़ित किया। बिहार की एक घटना में छात्रों को सजा देने के लिये एक कमरे में बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की एक घटना में छात्र का कंधा ही टूट गया। ये घटनाएं संकेत दे रही हैं कि सुरक्षित बचपन का दावा कितना खोखला है। यूं तो छात्रों को प्रताड़ित करना कानून की दृष्टि से प्रतिबंधित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 17 शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध लगाती है। किशोर न्याय अधिनियम में बच्चों के साथ क्रूरता के लिये तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर चोट या गंभीर चोट पहुंचायी जाती है, तो आईपीसी की धाराओं में मुकदमा चलाने का प्रावधान है। फिर भी ऐसे कई मामलों में, निलंबन या बर्खास्तगी से आगे कार्रवाई शायद ही कभी आगे बढ़ती है। ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियां तभी होती हैं, जब समाज में जनाक्रोश सीमाएं लांघने लगता है। ऐसे केस में दोष सिद्धि तो और भी दुर्लभ होती है। यह स्थिति उन लोगों का हौसला बढ़ाती है जो इस पुरानी मान्यता को मानते हैं कि डर से ही अनुशासन संभव होता है। वास्तव में ऐसे कृत्य बालमन पर गहरा आघात करते हैं। बचपन में अपमान और हिंसा के निशान सीखने, आत्मविश्वास और विश्वास को कमजोर करते हैं। वास्तव में अधिकारियों को ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए। छात्रों से शारीरिक हिंसा के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर तुरंत कार्रवाई, अपराधियों की बर्खास्तगी तथा स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

वैश्विक उथल-पुथल के दौर में देश तलाशे अपनी भूमिका

> उथल-पुथल भरे मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में देश के लिए अपनी जगह व भूमिका की पहचान ज़रूरी है। खासकर संरक्षणवादी व वैश्वीकरण- विरोधी नीतियों के दौर में। बेशक 2008 के असैन्य परमाणु समझौते के बाद भारत-अमेरिका संबंधों में बेहतरी शुरू हुई थी। लेकिन गत मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद तल्खी बढ़ी जो अब भारी टैरिफ दरें, एच-1बी वीज़ा व चाबहार प्रतिबंध तक जारी है।

हालिया घटनाएं मुझे फिर से एक बार इस पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं कि वैश्विक परिदृश्य में खेले जा रहे सत्ता के खेल में भारत की जगह क्या हो और इसमें 'साउथ ब्लॉक' को क्या भूमिका निभाने की जरूरत है। पिछले कुछ वक्त से, राष्ट्रपति ट्रंप और उनका व्यक्तित्व जोकि अमेरिकी रणनीति को संचालित कर रहा है, इसको लेकर काफ़ी चर्चा जारी है। हालांकि यह एक कारक मात्र है, यह मान लेना कि इसका प्रभाव सब चीज़ों पर है, देश मामलों का अति सरलीकरण होगा; खासकर तब जबकि अमेरिका एक महाशक्ति है। शायद हमारी अपनी राजनीति, जो लंबे समय से संस्थागत होने की बजाय व्यक्ति पर टिकी है, हमें दूसरों को भी अपने इसी नज़रिए से देखने के लिए मजबूर करती है...मेरी राय में यह एक गंभीर चूक है। सर्वप्रथम, अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों को ही लीजिए। हालांकि पाकिस्तान कभी-कभी अमेरिका के लिए एक उद्दंड बालक जैसी समस्या रहा है (विशेषकर अल-क़ायदा और ओसामा बिन लादेन के दौर में), फिर भी यह मुल्क दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए अमेरिकी नीति में कुल मिलाकर एक अहम औजार रहा है। सोवियत संघ के विरुद्ध अफ़ग़ान मुजाहिदीन विद्रोह के दौरान पाकिस्तान ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद, अफ़ग़ानिस्तान पर अमेरिकी आक्रमण और तालिबान के साथ युद्ध के दौरान, पाकिस्तान ने रसद सहायता और ख़ुफ़िया जानकारी, दोनों प्रदान की, यानि इस तरह उसने तालिबान और हक्कानी नेटवर्क, दोनों के साथ, दोहरा खेल खेला, हालांकि

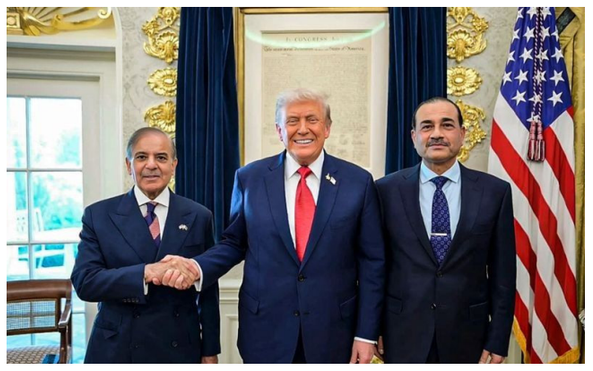

उसे इसकी भारी क़ीमत चुकानी पड़ी। 'पैटन' टैंकों से शुरू करते हुए और आगे चलकर एफ-16 लड़ाकू विमान देना, पाकिस्तानी सेना को भी ज्यादातर अमेरिका ने ही सुसज्जित और प्रशिक्षित किया। बेशक,हालिया वर्षों में, उसे चीन के रूप में एक मज़बूत समर्थक भी मिल गया। मैं इस पुराने संबंध का ज़िक्र इस क्षेत्र में अमेरिका के रहे (और आज भी) रणनीतिक हितों पर प्रकाश डालने के लिए कर रहा हूं। अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अफ़ग़ानिस्तान से बगराम एयरबेस अमेरिका को सौंपने की मांग की है, जो इसका संकेत है कि जल्द ही कोई कड़ी कार्रवाई होने वाली है। सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध और विशेष रूप से तीनों सेनाओं में रूस निर्मित हथियार और गोला-बारूद की आमद के चलते (हमारे अधिकांश पुराने उपकरण रूसी हैं) 20वीं सदी के अधिकांश समय में भारत-अमेरिका संबंधों को ठंडा या ज्यादा-से-ज्यादा गुनगुना ही कहा जा सकता है। सोवियत संघ विघटन और भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने से अमेरिका के साथ एक नई शुरुआत के लिए अनुकूल माहौल बना। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते ने भारत पर दशकों से लगे परमाणु प्रौद्योगिकी प्रतिबंध को खत्म करवाया और साथ ही एक तरह से परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र होने की मान्यता भी मिली। इससे भारत-अमेरिका संबंधों को काफी सकारात्मक गति मिली। राष्ट्रपति ट्रम्प के पहले कार्यकाल में, भारत-अमेरिका संबंध सुधरते दिख रहे था। हालांकि, इस वर्ष संकेत तब अशुभ हो गए, जब मई में हुई सैन्य झड़प के बाद - जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए पहलगाम नरसंहार के बाद हुई थी – ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धविराम पर सहमति बनवाने का दावा किया। भारत ने इसका खंडन किया व स्पष्ट किया कि युद्धविराम दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच वार्ता से बना। इसके बाद, ट्रम्प ने बारंबार युद्धविराम करवाने का दावा किया और कहा कि इस तरह उन्होंने एक संभावित परमाणु संघर्ष को टलवाया। स्थिति और मुश्किल बन गयी जब ट्रंप ने पाक सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर को निजी लंच दिया (अमेरिका ने बाद में भी उनकी मेज़बानी की)। किसी देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हुए उसके सेना प्रमुख को न्योता देना अपनी ही कहानी बयां करता है। न्योता तो हमारे प्रधानमंत्री को भी दिया गया था, जब वे कनाडा में थे, लेकिन उन्होंने पहले से तय कार्यक्रमों में व्यस्तता के चलते मना कर दिया (मौजूदा व्हाइट हाउस वासियों ने इसे हल्के में नहीं लिया होगा)। पिछले साल अपनी चुनावी रैलियों में, ट्रंप ने भारत को 'टैरिफ किंग' ठहराया था और भारत तथा अन्य देशों पर, जिनके बारे में उनका दावा था कि अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन और व्यवहार में भारी अंतर हैं, उन पर तगड़ा टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अंततः भारी टैरिफ लगा भी दिया; पहले 25 फीसदी , जो अपमानजनक है क्योंकि चीन को छोड़ हमारे पड़ोसी एशियाई देशों पर टैरिफ बहुत कम है और फिर रूसी तेल खरीदने पर अतिरिक्त 25 फीसदी (कुल 50 प्रतिशत तक निषेधात्मक) लगा दिया। किसी कारण, हमारे विदेश और वाणिज्य मंत्रालय के अलावा मीडिया का बड़ा वर्ग इस मंडराते खतरे को नकारता दिखाई दिया, इस उम्मीद में कि हमारे नेताओं के व्यक्तिगत संबंधों से स्थिति संभाल ली जाएगी। फिलहाल ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हमारी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध और अधिक दंडात्मक उपायों की धमकी न दी जाती हो। एच-1बी वीज़ा प्रकरण (1,00,000 डॉलर शुल्क) हमारे ऊपर नवीनतम प्रहार है। इसका प्रभाव हमारी आईटी फर्मों और पेशेवरों पर दीर्घ काल में बहुत बड़ा रहेगा। हमें इन उच्च प्रशिक्षित पेशेवरों को किसी अन्य देश के हित में फिर से खो देने के बजाय, इनकी संभावित वतन वापसी हेतु अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो, हमें क्यों अलग-थलग करने के साथ निशाना बनाया जा रहा है? क्या यह मुख्यतः रूसी तेल का मामला है? अगर ऐसा होता, तो यूरोप और कई नाटो देश भी इसके दोषी होते। अगर नहीं, तो क्या हम एक बहुत बड़े खेल में 'मोहरा' बन रहे हैं? शोचनीय है , सऊदी-पाक सैन्य समझौता इतनी जल्दी कैसे संभव है? अमेरिका के आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं। ईरान में चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंधों में ढील वापस लेना हम पर किया गया अन्य आघात रहा। यह बंदरगाह इस क्षेत्र में हमारे प्रमुख रणनीतिक हितों में से एक था और इससे हमें मध्य एशियाई बाजारों और अफ़ग़ानिस्तान तक पहुंचने में मदद मिलती। हो सकता है अमेरिका द्वारा ईरान पर हाल में की गई बमबारी और अमेरिका-पाकिस्तान के बीच हो रहे समझौतों ने इस पर असर डाला हो। संभवतः ये कदम इस क्षेत्र में बढ़ रहे चीनी प्रभाव का मुकाबला करने को उठाए जा रहे हों। चीन ईरानी तेल का बड़ा खरीदार है। चीन और अफ़ग़ानिस्तान दुर्लभ धातु अयस्क खनन पर समझौते कर रहे हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इस क्षेत्र से गुज़रती है - इसमें कई खेल संभव हैं। मैं अपने निकटतम पड़ोस पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा।

प्रेरणा

कल्पना और साहस की अनोखी यात्रा : चार्ली चैपलिन का जीवन

गरीबी, संघर्ष और निराशा से घिरा हुआ एक छोटा-सा लड़का, जिसकी दुनिया केवल उसकी मां और बड़े भाई तक सीमित थी, आगे चलकर ऐसा कलाकार बना जिसकी हंसी पूरी दुनिया के दिलों तक पहुंची। यह कहानी है चार्ली चैपलिन की, जिन्होंने अपने शुरुआती जीवन की मुश्किलों को कल्पना और साहस के सहारे महानता में बदल दिया। चार्ली का जन्म ऐसे घर में हुआ जहाँ हर दिन जीवनयापन की जद्दोजहद थी। पिता ने परिवार से किनारा कर लिया था और मां हाना चैपलिन अकेले बच्चों को पाल रही थीं। उनका परिवार कई बार भूखा सोता, कई बार चर्च से मिलने वाली सहायता पर जिंदा रहता। कभी-कभी तो शो की टिकटें बेचकर ही पेट भरने का इंतजाम होता। लेकिन इन सबके बावजूद, उनकी मां ने कभी अपने बच्चों को टूटने नहीं दिया। हाना खुद एक स्टेज आर्टिस्ट थीं, लेकिन बीमारी ने उनका करियर छीन लिया। इसके बावजूद उन्होंने चार्ली को यह अनमोल सीख दी कि इंसान की असली ताकत उसके जेब में पड़े पैसों से नहीं, बल्कि उसके मन और कल्पना की शक्ति से मापी जाती है। चैपलिन जब छोटे थे, तो अक्सर अपनी मां को खिड़की पर बैठकर राहगीरों को

देखते हुए पाते। वे लोगों की चाल-ढाल, हावभाव और बोलचाल की नकल करतीं और अपने बच्चों को उनसे कहानियां सुनातीं। यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी—किसी भी परिस्थिति को ध्यान और कल्पना से कला में बदल देना। यह आदत धीरे-धीरे चार्ली की नस-नस में उतर गई। वे लोगों की चाल देखकर उनके चरित्र गढ़ते, उनकी नकल उतारते और उन पर मजाकिया कहानियां रचते। यही गुण आगे चलकर उनके अभिनय का आधार बने। परिवार की तंगी ने चार्ली को जल्दी ही जिम्मेदारियां थमा दीं। उनका बड़ा भाई सिडनी अखबार बेचता और पढ़ाई करता, लेकिन जरूरतें पूरी नहीं हो पातीं। चार्ली भी छोटे-छोटे काम करते—कभी अखबार बेचते, कभी छोटे-मोटे नाटक में हिस्सा लेते। जिंदगी कठिन थी, मगर इसी कठिनाई ने उन्हें सिखाया कि दुख को हंसी में बदलना सबसे बड़ा साहस है। चैपलिन का मानना था कि ऐशो-आराम की लत जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। वे कहते थे—"जिंदगी खूबसूरत हो सकती है, अगर आप इससे डरें नहीं। ज़रूरत है बस थोड़े से पैसों, थोड़े से साहस और ढेर सारी कल्पना की।" यह सोच ही उन्हें भीड़ से अलग बनाती थी। जब वे फिल्मों में आए, तो उनका हर किरदार साधारण इंसान की तकलीफों, परेशानियों और मज़ाकिया संघर्षों का चित्रण करता। दुनिया के करोड़ों लोग उनकी फिल्मों में अपने ही जीवन की झलक देखते और हंसते हुए अपनी परेशानियां भूल जाते। चैपलिन की एक और अमर सीख थी—"अगर आप नीचे देखेंगे, तो कभी भी इंद्रधनुष नहीं देख पाएंगे।" वे मानते थे कि जिंदगी लगातार बदलती रहती है और इस परिवर्तन में हमारी परेशानियां भी स्थायी नहीं हैं। यही विश्वास उन्हें हमेशा आगे बढ़ाता रहा। चार्ली चैपलिन का जीवन हमें यह सिखाता है कि कल्पना इंसान के भीतर की सबसे बड़ी दौलत है। यह गरीबी, भूख और दुःख से भी बड़ी ताकत है। और साहस वह ऊर्जा है, जो इंसान को गिरने के बाद फिर उठ खड़ा करती है। अगर हम जीवन को हंसते हुए जीना सीख लें, तो मुश्किलें भी अवसर में बदल जाती हैं। यही चैपलिन की सबसे बड़ी विरासत है—हंसी के जरिए साहस और कल्पना की शक्ति को अमर करना।

खैबर पख्तूनख्वा में Lashkar-e-Taiba को बसाने के लिए Tehreek-e-Taliban Pakistan का सफाया कर रही पाकिस्तानी सेना

पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई लंबे समय से आतंकवाद को रणनीतिक साधन की तरह इस्तेमाल करती रही है। अफगानिस्तान से लेकर भारत तक, उसने ऐसे आतंकी संगठनों को समर्थन दिया जिनसे उसे भू-राजनीतिक लाभ मिल सके। अब ताज़ा घटनाक्रम बताता है कि पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा (KPK) प्रांत में एक नया क्लीन-अप ड्राइव शुरू किया है, जिसका घोषित उद्देश्य है— तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का खात्मा। लेकिन इसके पीछे का वास्तविक मकसद है— लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के लिए सुरक्षित ठिकाना तैयार करना। सवाल उठता है कि लश्कर के लिए सुरक्षित जगह क्यों तलाशी जा रही है? हम आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा, खासकर लोअर दिर और तिराह घाटी, पाकिस्तान तालिबान का गढ़ मानी जाती है। लेकिन ISI की योजना है कि इसी क्षेत्र को लश्कर और हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे भारत-विरोधी आतंकी संगठनों का नया केंद्र बनाया जाए। दरअसल, लश्कर की विचारधारा अहले-हदीस पर आधारित है और वह पाकिस्तानी डीप स्टेट के लिए वफादार है। इसके विपरीत, TTP कट्टर देओबंदी और पाकिस्तान विरोधी संगठन है। इस वैचारिक और राजनीतिक टकराव के कारण TTP ने अतीत में लश्कर के कमांडरों पर हमले किए और 2011 में लोअर दिर में अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की लश्कर की कोशिश आत्मघाती बम विस्फोट में ध्वस्त हो गई। यही वजह है कि अब सेना पहले TTP को हटाने की कवायद कर रही है ताकि लश्कर के लिए साफ़ मैदान तैयार हो सके। यहां सवाल यह भी उठता है कि क्या पाकिस्तान अच्छे और बुरे आतंकवाद के बीच चयन कर रहा है? देखा जाये तो यह घटनाक्रम पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीति को उजागर करता है। पाकिस्तान की नजर में अच्छा आतंकवाद वह है जिसे इस्लामाबाद भारत या अफगानिस्तान में इस्तेमाल कर सके और जो ISI के हितों के अनुरूप काम करे। जैसे लश्कर-ए-तैयबा या हिज्बुल मुजाहिदीन। साथ ही इस्लामाबाद की नजर में बुरा आतंकवाद वह है जो पाकिस्तान के ही खिलाफ़ खड़ा हो जाए और उसकी नीतियों को चुनौती दे। जैसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। हम आपको यह भी बता दें कि क्लीन-अप ड्राइव में दर्जनों नागरिकों की मौत इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान का असली लक्ष्य आतंकवाद मुक्त क्षेत्र बनाना नहीं, बल्कि अपने पाले हुए संगठनों के लिए रास्ता साफ़ करना है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान की इस कार्रवाई से अगर TTP भड़क गया तब क्या होगा? देखा जाये तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा यही है कि अगर TTP पूरी ताक़त से पलटवार करता है, तो KPK और संघीय इलाक़ों में हिंसा बेकाबू हो सकती है। TTP पहले ही सेना, पुलिस और प्रशासनिक ठिकानों पर हमले करता रहा है। यदि उसे यह अहसास हुआ कि सेना लश्कर के लिए जगह बनाने के लिए उसका सफाया कर रही है, तो वह और उग्र हो सकता है। इससे पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा बुरी तरह प्रभावित होगी। साथ ही पाकिस्तानी सेना को एक साथ दो मोर्चों— भीतरी विद्रोह और आतंकी अभियानों पर लड़ना पड़ेगा। इससे पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि और कमजोर होगी, क्योंकि यह साफ़ हो जाएगा कि उसका असली उद्देश्य आतंकवाद खत्म करना नहीं, बल्कि अपने पसंदीदा आतंकियों को बचाना और बढ़ावा देना है। हम आपको यह भी बता दें कि कश्मीर में भारत की कठोर आतंक-रोधी कार्रवाइयों और FATF जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव ने लश्कर की गतिविधियों को सीमित कर दिया है। पाकिस्तान जानता है कि यदि लश्कर को जीवित रखना है, तो उसे नए प्रशिक्षण केंद्र और सुरक्षित ठिकाने चाहिए। KPK का इलाका इसके लिए मुफीद माना जा रहा है क्योंकि भूगोल दुर्गम है, जिससे बाहरी नज़र रखना मुश्किल होता है। साथ ही तालिबान की मौजूदगी से चरमपंथी माहौल पहले से तैयार है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की पकड़ वहाँ मजबूत है, जिससे अंतरराष्ट्रीय निगरानी को छकाया जा सके। देखा जाये तो पाकिस्तान की ताज़ा रणनीति यह दिखाती है कि वह आज भी आतंकवाद को अपनी विदेश नीति और सुरक्षा नीति का अभिन्न हिस्सा मानता है। TTP का खात्मा केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि लश्कर और हिज्बुल जैसे संगठन भारत-विरोधी अभियानों के लिए मजबूत हो सकें। बहरहाल, यह अच्छे और बुरे आतंकवाद का खतरनाक खेल है, जो न सिर्फ पाकिस्तान की आंतरिक शांति को निगल जाएगा, बल्कि दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए भी गंभीर चुनौती बनेगा। यदि TTP ने बदले की कार्रवाई तेज़ की, तो पाकिस्तान के लिए यह नीति आत्मघाती साबित होगी।

अभियान

बिहार से निकला वो आंदोलन जिसने मोहनदास को महात्मा बनाया

भारत की स्वतंत्रता संग्राम की विशाल गाथा में यदि किसी एक घटना को गांधी जी के जीवन का निर्णायक मोड़ कहा जाए तो वह 1917 का चंपारण सत्याग्रह है। यह वही आंदोलन था जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को "महात्मा" के रूप में भारतीय जनमानस की चेतना में स्थापित कर दिया। गांधी जी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने रंगभेद और भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध दो दशक तक सत्य और अहिंसा का संघर्ष किया था। वह संघर्ष उनके जीवन की प्रयोगशाला था, लेकिन भारत की भूमि पर उनका पहला प्रयोग होना बाकी था। इस प्रयोग के लिए परिस्थितियाँ बिहार के चंपारण में तैयार हो चुकी थीं। उस समय चंपारण के किसानों पर अंग्रेज़ों ने एक अमानवीय प्रथा थोप रखी थी जिसे तिनकठिया प्रथा कहा जाता था। इसके अंतर्गत किसानों को मजबूर किया जाता कि वे अपनी भूमि का 3/20 हिस्सा केवल नील की खेती में लगाएँ। यह नील अंग्रेजों के व्यापार का केंद्र था, लेकिन किसानों के लिए यह खेती अभिशाप बन गई थी। नील की फसल जमीन को बर्बाद कर देती और खाद्यान्न की पैदावार घट जाती। ऊपर से जबरदस्ती, मारपीट और कर्ज़ का बोझ किसानों को भूख और बदहाली की ओर धकेल देता। चंपारण निवासी राजकुमार शुक्ल इन अत्याचारों को देखकर व्याकुल थे। उन्होंने निश्चय किया कि कोई बड़ा नेता यहाँ आकर किसानों की आवाज़ बने। वे पहले बाल गंगाधर तिलक और फिर मदन मोहन मालवीय के पास गए, लेकिन दोनों अपनी व्यस्तताओं के कारण नहीं आ सके। अंततः शुक्ल गांधी जी के पास पहुँचे और उनसे चंपारण चलने की प्रार्थना की। गांधी जी ने शुक्ल की दृढ़ता और किसानों की करुण दशा को समझा और अप्रैल 1917 में बिहार की धरती पर कदम रखा। 10 अप्रैल को वे मुजफ्फरपुर पहुँचे, जहाँ विद्यार्थियों और प्रोफेसरों ने उनका भव्य स्वागत किया। 15 अप्रैल को उन्होंने चंपारण का रुख किया। चंपारण पहुँचकर गांधी जी ने पाया कि

किसानों की दयनीय स्थिति केवल नील प्रथा तक सीमित नहीं थी। गाँवों में गंदगी का अम्बार था, शिक्षा का कोई साधन नहीं, स्वास्थ्य सेवाएँ नगण्य और जनता पूरी तरह निराश। गांधी जी ने अंग्रेजों से तो लड़ाई छेड़ी ही, साथ ही स्थानीय जनता को भी आत्मसुधार के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गाँवों की सफाई कराई, कुओं की व्यवस्था सुधारी, स्कूल खुलवाए और लोगों में स्वाभिमान की चेतना जगाई। जब गांधी जी किसानों की समस्याओं को दर्ज करने लगे तो अंग्रेजी हुकूमत चौंक गई। उन्होंने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया और उन पर मुकदमा चला। लेकिन जनता की भारी भीड़ अदालत के बाहर इकट्ठा हो गई। दबाव इतना बढ़ा कि अंग्रेजों को मुकदमा वापस लेना पड़ा। यह गांधी जी और किसानों की पहली जीत थी। इसके बाद प्रांतीय सरकार को किसानों पर अत्याचारों की जांच के लिए एक समिति गठित करनी पड़ी, जिसमें गांधी जी को शामिल किया गया। चंपारण सत्याग्रह का प्रभाव गहरा और दूरगामी था। पहली बार किसानों की समस्या ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लिया। अंग्रेजों को झुकना पड़ा और धीरे-धीरे तिनकठिया प्रथा समाप्त कर दी गई। इससे किसानों में आत्मविश्वास जागा और पूरे भारत में यह संदेश गया कि सत्याग्रह और अहिंसक प्रतिरोध अंग्रेज़ी साम्राज्य को भी चुनौती दे सकता है। यही कारण है कि इतिहासकार मानते हैं कि चंपारण गांधी जी की प्रयोगशाला था। यहाँ उन्होंने अपने सिद्धांतों को परखा और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया शस्त्र दिया — सत्याग्रह। यही वह क्षण था जब मोहनदास करमचंद गांधी जनता की नज़रों में "बापू" और "महात्मा" बन गए। आज इस घटना को 107 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन यह आंदोलन आज भी हमें याद दिलाता है कि संगठित जनशक्ति और अहिंसा के मार्ग पर चलकर सबसे बड़ी ताकतों को भी झुकाया जा सकता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

जगन्नाथ पुरी धाम के अनसुने किस्से: PM को भी नहीं मिली थी प्रवेश की अनुमति

जगन्नाथ पुरी धाम भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है, जो भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, यह वही स्थान है जहाँ वैकुंठ लोक का एक हिस्सा धरती पर आया और भगवान विष्णु ने धरती पर अपने दिव्य रूप में वास किया। इस मंदिर का इतिहास और इसकी स्थापना की कथाएँ अत्यंत रोचक हैं। कहा जाता है कि उत्कल क्षेत्र के राजा इंद्र देव और उनकी पत्नी रानी गुंडजा ने भगवान नीलमाधव के लिए मंदिर बनवाने का प्रयास किया। इस कार्य में हनुमान जी ने भी उनकी मदद की और देव विश्वकर्मा ने बूढ़े शिल्पकार के रूप में आकर भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाएँ तैनात की।

मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विषय भी अत्यंत रोचक है। जब यह तय हुआ कि किस ब्राह्मण को प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, तब देवर्षि नारद प्रकट हुए और सुझाव दिया कि ब्रह्मा जी को ही यह कार्य करना चाहिए। राजा इंद्र देव ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी से अनुमति प्राप्त कर लौटे। इस दौरान धरती पर कई सदियाँ बीत चुकी थीं और मंदिर समय की परतों में रेत के नीचे दब गया था। एक दिन समुद्री तूफान आया और मंदिर का शिखर रेत से बाहर आया। राजा इंद्रदेव और रानी गुंडजा ने ब्रह्मा जी की उपस्थिति में यज्ञ कराकर भगवान जगन्नाथ की प्राण प्रतिष्ठा की। इसी अवसर पर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र ने प्रकट होकर राजा-रानी को कई वरदान दिए। रथ यात्रा की परंपरा इसी दिन से शुरू हुई और आज भी आषाढ़ शुक्त पक्ष की द्वितीय तिथि को इसे भव्य रूप से मनाया जाता है।

जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश के नियम भी अत्यंत विशिष्ट हैं। वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। इसका कारण यह था कि मंदिर में केवल सनातन हिन्दुओं को प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इंदिरा गांधी का विवाह पारसी धर्म के फिरोज जहांगीर गांधी से हुआ था, इसलिए तकनीकी रूप से उन्हें हिन्दू नहीं माना गया और प्रवेश से वंचित रखा गया। इसके अलावा वर्ष 2005 में थाईलैंड की रानी को और 2006 में स्विजरलैंड की एक नागरिक को भी धार्मिक या विदेशी होने के कारण प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। इस्कॉन संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के अनुयायियों को भी मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। मंदिर में प्रवेश के नियमों को शिलापट्ट पर पांच भाषाओं में लिखा गया है, जिसमें साफ तौर पर उल्लेख है कि केवल सनातन हिन्दू ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं।

जगन्नाथ मंदिर का इतिहास विदेशी आक्रमणों और संघर्षों से भी भरा हुआ है। इसे 20 बार विदेशी हमलावरों द्वारा लूटा गया। विशेषकर मुस्लिम सुल्तानों और बादशाहों ने ओडिशा पर हमला कर मंदिर की मूर्तियों को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियों को बार-बार छुपाकर सुरक्षित रखा। कभी मूर्तियों को ओडिशा से बाहर ले जाकर हैदराबाद में भी सुरक्षित रखा गया। इन हमलों और लूटपाट की वजह से भगवान जगन्नाथ को 144 वर्षों तक मंदिर से दूर रहना पड़ा।

जगन्नाथ पुरी धाम केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी अत्यंत महान है। यह मंदिर न केवल हिंदू धर्मावलंबियों के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। मंदिर के प्रबंधन और नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि इसकी पवित्रता और परंपराओं का संरक्षण हो। हर साल आयोजित रथ यात्रा, महा आरती और अन्य धार्मिक अनुष्ठान लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। यह मंदिर भारतीय संस्कृति, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक गौरव का अनमोल प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।

दिवाली और छठ पर्व पर छत्तीसगढ़वासियों के लिए रेलवे की खास सुविधा, चलेगी स्पेशल ट्रेन

रायपुर। दिवाली और छठ पर्व के मौके पर छत्तीसगढ़ में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक विशेष पहल की है। यात्रियों की सुविधा और भीड़ को कम करने के उद्देश्य से रेलवे ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जंक्शन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह कदम उन लोगों के लिए राहत साबित होगा जो पर्व के अवसर पर अपने परिवार से मिलने और उत्सव मनाने के लिए यात्रा करते हैं।

रेलवे द्वारा जारी विवरण के अनुसार, ट्रेन नंबर 08760 हजरत निजामुद्दीन से दुर्ग जंक्शन के लिए हर रविवार को सुबह 10.45 बजे चलेगी। यह ट्रेन 5 अक्तूबर से 23 नवंबर तक सेवाओं के लिए उपलब्ध रहेगी और अगले दिन सुबह 11.10 बजे दुर्ग जंक्शन पहुंच जाएगी। वापसी में ट्रेन नंबर 08761 हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से हर सोमवार दोपहर 12.30 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 3 बजे दुर्ग जंक्शन पहुंचेगी।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस विशेष ट्रेन का संचालन विशेष रूप से दिवाली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए किया जा रहा है। इससे न केवल यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा, बल्कि सड़क मार्ग पर होने वाली भीड़ और यातायात जाम को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

रेलवे ने लोगों से अपील की है कि वे टिकटों के लिए समय पर आरक्षण कर लें क्योंकि पर्व के समय यात्रा करने वालों की संख्या अधिक होने की संभावना है। इस स्पेशल ट्रेन के संचालन से छत्तीसगढ़ और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को पर्व के दौरान सुविधा और समय की बचत दोनों का लाभ मिलेगा।

इस पहल से यह स्पष्ट है कि भारतीय रेलवे ने न केवल यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता दी है, बल्कि पर्वों के दौरान देशभर में यात्रा के अनुभव को भी बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

अक्षय खन्ना का दमदार अवतार: फिल्म 'महाकाली' में असुर गुरु शुक्राचार्य के रूप में आएंगे नजर

अक्षय खन्ना ने भारतीय सिनेमा में हमेशा ही अपनी विशिष्ट भूमिकाओं और चुनौतीपूर्ण किरदारों के लिए पहचान बनाई है। 'छावा' में औरंगजेब के किरदार से तहलका मचाने के बाद अब वह पौराणिक कथाओं पर आधारित नई फिल्म 'महाकाली' में असुर गुरु शुक्राचार्य की भूमिका निभाने जा रहे हैं। फिल्म का पहला लुक सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया और फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया। अक्षय खन्ना के इस किरदार में उनके लंबे सफेद बाल, घनी दाढ़ी और गंभीर चेहरे ने असुर गुरु की तीव्रता, शक्ति और भव्यता को दर्शाते हुए उनके किरदार को अत्यंत प्रभावशाली बना दिया है। फिल्म के निर्देशक प्रशांत वर्मा, जिन्होंने पहले ब्लॉकबस्टर 'हनुमान' बनाई थी, इस बार भी पौराणिक कथाओं को बड़े पर्दे पर जीवंत रूप में पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। 'महाकाली' को प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा माना जा रहा है और इसमें देवताओं और असुरों के संघर्ष को बड़े सिनेमैटिक दृष्टिकोण के साथ दिखाया जाएगा। निर्देशक ने कहा कि यह फिल्म न केवल पौराणिक कथाओं के रोमांचक पहलुओं को उजागर करेगी बल्कि अक्षय खन्ना की अभिनय क्षमता को भी नई ऊँचाईयों पर ले जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म में असुर गुरु के रूप में अक्षय खन्ना का किरदार शाश्वत पौराणिक चरित्रों की गहराई और उनकी विद्रोही शक्ति को दर्शाएगा। फिल्म में अन्य कलाकारों के नाम अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन अनुमान है कि बड़े सितारे अक्षय खन्ना के साथ पर्दे पर धमाल मचाने वाले हैं। फैंस और फिल्म प्रेमियों की उत्सुकता इस बात को लेकर चरम पर है कि अक्षय के इस किरदार के साथ कौन-कौन से सितारे स्क्रीन साझा करेंगे। पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्मों में आमतौर पर अभिनय, दृश्य और सेट डिज़ाइन की उच्च गुणवत्ता की उम्मीद की जाती है और 'महाकाली' इसे और भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। अक्षय खन्ना के इस किरदार को लेकर फैंस का मानना है कि यह भूमिका उन्हें उनके करियर के लिए एक नया मुकाम दिलाएगी और उनकी क्षमता को साबित करेगी कि वह किसी भी चुनौतीपूर्ण भूमिका को निभा सकते हैं। फिल्म के रोमांचक दृश्य, विशेष प्रभाव और गहन कथानक दर्शकों को पुराने पौराणिक चरित्रों के साथ-साथ नए दृष्टिकोण से भी परिचित कराएंगे। फिल्म के निर्माण पक्ष का कहना है कि 'महाकाली' भारतीय पौराणिक सिनेमा में नई परिभाषा स्थापित करेगी। अक्षय खन्ना की दमदार उपस्थिति, असुर गुरु के किरदार की गहनता और प्रशांत वर्मा की निर्देशन शैली मिलकर दर्शकों को एक ऐसा सिनेमैटिक अनुभव देंगे, जो लंबे समय तक याद रहेगा। इस फिल्म के जरिए पौराणिक कथाओं को आधुनिक दृष्टिकोण और सिनेमाई तकनीक के साथ पेश करना एक बड़ा प्रयास है, और इसके सफल होने की उम्मीद दर्शकों और आलोचकों दोनों के लिए बहुत उत्साहजनक है।

बदलापुर छात्राओं से दुराचार मामले के बाद हाई कोर्ट सख्त, सभी स्कूलों को सुरक्षा अनुपालन डेटा अपलोड करने का निर्देश

बदलापुर में छात्राओं के साथ हुए दुराचार मामले ने पूरे राज्य में स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए थे। इसी मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। मंगलवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने अदालत को जानकारी दी कि अब तक 40 प्रतिशत स्कूलों का सुरक्षा और अनुपालन से जुड़ा डेटा विशेष रूप से तैयार की गई वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा चुका है।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति संदेश डी. पाटिल की खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य शिक्षा विभाग 9 अक्टूबर 2025 तक सभी स्कूलों, आश्रमशालाओं, आंगनवाड़ियों और संप्रेक्षण गृहों का सुरक्षा अनुपालन विवरण वेबसाइट पर अपलोड करे। अदालत ने यह भी कहा कि यह केवल आंकड़े भरने की प्रक्रिया न हो, बल्कि समिति की सभी सिफारिशों का वास्तविक पालन भी सुनिश्चित किया जाए।

सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस उद्देश्य से एक पोर्टल तैयार किया गया है, जिस पर प्रत्येक संस्थान को अपने सुरक्षा इंतज़ामों से संबंधित विवरण अपलोड करना है। इसमें स्कूल सुरक्षा समिति का गठन, सीसीटीवी की स्थिति, प्रवेश-निकास की निगरानी व्यवस्था, महिला स्टाफ की उपस्थिति और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी अन्य व्यवस्थाएं शामिल होंगी।

अदालत ने यह टिप्पणी भी की कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा यह मामला केवल एक औपचारिकता नहीं हो सकता। पिछले साल बदलापुर की घटना के बाद यह ज़रूरी है कि स्कूलों में सुरक्षा इंतज़ामों को गंभीरता से लागू किया जाए और उनकी पारदर्शी निगरानी हो।

सरकारी आंकड़ों से यह भी सामने आया कि राज्य के 61,621 सरकारी स्कूलों में से 2,266 स्कूलों में अभी सुरक्षा समिति का गठन बाकी है। वहीं, निजी और सहायता प्राप्त 44,435 स्कूलों में से 33,296 स्कूलों में सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं, लेकिन 11,139 स्कूलों में अभी तक नहीं लगाए गए हैं। सरकारी स्कूलों में स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है, जहां 18,572 स्कूलों में सीसीटीवी लगाए गए हैं, जबकि 45,315 में यह काम लंबित है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। तब तक अदालत ने सरकार को साफ निर्देश दिया है कि सुरक्षा से जुड़ी सारी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाए और अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कदम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समाज में भरोसा बहाल करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

MP के मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ाया जा रहा कुरान, NHRC ने उठाया अलार्म

भोपाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी जिलों में सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों में हिंदू बच्चों के दाखिले पर गंभीर चिंता जताई है। कानूनगो के अनुसार लगभग 500 हिंदू बच्चों को कथित तौर पर कुरान और अन्य इस्लामी शिक्षाएँ पढ़ाई जा रही हैं, जिससे उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित करने की साजिश के आरोप लगे हैं।

कानूनगो ने बताया कि उन्हें इस मामले में कई शिकायतें मिली हैं और उन्होंने इसे जाँच के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेजा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू बच्चों का मदरसों में नामांकन नहीं होना चाहिए और मुस्लिम बच्चों को भी अपनी बुनियादी शिक्षा के लिए स्कूल में दाखिला मिलना आवश्यक है। कानूनगो ने कहा, "मदरसा बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने की जगह है, स्कूल नहीं। अगर मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, तो उन्हें स्कूल में भी शिक्षा दी जानी चाहिए।"

एनएचआरसी सदस्य ने यह भी दावा किया कि यह स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(3) का उल्लंघन है, जो सरकारी धन से संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। उन्होंने कहा कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो राज्य सरकार को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

मध्य प्रदेश सरकार को NHRC ने 15 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राज्य में एक सुसंगठित अवैध धर्मांतरण रैकेट 556 हिंदू बच्चों को 27 अनधिकृत मदरसों में दाखिला दिलाकर इस्लाम में धर्मांतरित करने का प्रयास कर रहा है। इस मामले की गहन जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बहराइच में भेड़ियों का आतंक फिर सक्रिय, बुजुर्ग दंपति शिकार

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का आतंक अब एक बार फिर लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। मंगलवार को कैसरगंज रेंज के मंझारा तौकली गांव में एक भेड़िये ने बुजुर्ग दंपति को अपना शिकार बना लिया। मृतक दंपति की पहचान खेदन (75) और मनखिया (70) के रूप में हुई है। वे रात को अपने खेत की रखवाली कर रहे थे, तभी भेड़िये ने उन पर हमला किया और उनके शरीर के ऊपरी हिस्से को नुकसान पहुँचाया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने नाराजगी में वन विभाग के वाहन को तोड़ दिया। पुलिस और वन विभाग की जानकारी के अनुसार, अब तक बहराइच जिले के मक्का पुरवा, नकवा गांव, कुलैला, हिंद सिंह गांव, महसी और सिसैया चूड़ामणि समेत कई क्षेत्रों में भेड़ियों ने 17 लोगों पर हमला किया है। इन हमलों में 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें चार बच्चे भी शामिल हैं।

भावनगर के सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना में हिंदी पखवाड़ा – 2025 का सफल समापन

हिंदी पखवाड़ा – 2025 के अंतर्गत दो सप्ताह तक आयोजित हुई राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताएँ और गतिविधियाँ

भावनगर परा स्थित पश्चिम रेलवे के सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना के राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 15-09-2025 से 29-09-2025 तक हिंदी पखवाड़ा – 2025 धूमधाम से मनाया गया। पखवाड़े में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। कारखाने के सभी अधिकारियों – कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। 15 सितंबर से शुरू हुए इस पखवाड़े का समापन 29 सितंबर, 2025 को पुरस्कार वितरण कर किया गया।

पश्चिम रेलवे के सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना के राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। आज हिंदी पखवाड़े के समापन अवसर पर कारखाने के उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर श्री सौरभ सिंह ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के पश्चात भावनगर परा स्थित रेलवे के सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाने में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए यह पखवाड़ा मनाया जाता है।

पखवाड़े के दौरान अधिकारियों के लिए राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता और फोटो कैप्शन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। साथ ही, कर्मचारियों के लिए अपनी पसंद अपनी प्रस्तुति, हिंदी टिप्पण सह सुलेखन और हिंदी निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। 15 सितंबर को पखवाड़े की विधिवत शुरुआत की गई थी और 29 सितम्बर को पखवाड़े में आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण करके इसका सफल समापन किया गया।

राजभाषा विभाग की ओर से सहायक वित्त सलाहकार एवं संपर्क राजभाषा अधिकारी श्री रत्नेश कुमार ने बताया कि हिंदी पखवाड़े के आयोजन का उद्देश्य अधिकारियों-कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी से जुड़े संवैधानिक दायित्वों के प्रति जागरुक करना और उन्हें सभी कार्यालयीन कार्य राजभाषा हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। श्री रत्नेश कुमार ने बताया कि 29 सितंबर को सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करके इस पखवाड़े का विधिवत समापन किया गया। इस दौरान अधिकारियों-कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में काम करने में मदद करने के साथ ही उन्हें इससे जुड़ी जानकारी भी प्रदान की जाती है।

भावनगर रेलवे मंडल पर "राजभाषा माह-2025" का सफल आयोजन

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल पर 14 सितंबर के अवसर पर मंडल कार्यालय तथा महत्वपूर्ण स्टेशनों पर हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। भावनगर के मंडल कार्यालय में दिनांक:01-09-2025 से दिनांक:30-09-2024 तक राजभाषा माह 2025 मनाया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों के लिए 04 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई. इन प्रतियोगिताओं में 102 कर्मचारियों ने बडे उत्साह से भाग लिया। इसके अलावा विभागवार राजभाषा प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी जिसमें सभी विभागों ने अपने-अपने विभागों में किए जा रहे हिंदी कार्यों को प्रदर्शित किया था। मंडल कार्यालय के अलावा स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति – भावनगर टर्मिनस, भावनगर परा, धोला, बोटाद, जेतलसर, जूनागढ़, वेरावल तथा पोरबंदर द्वारा भी हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। इस तरह समग्र भावनगर मंडल पर राजभाषा हिंदी का उत्साह से परिपूर्ण एवं अभूतपूर्व वातावरण बन गया है। भावनगर रेलवे मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडल कार्यालय में दिनांक: 30-09-2024 को राजभाषा माह 2025 का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जिसमें प्रतियोगिता के विजेताओं, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ-साथ इस आयोजन में सहयोग करने वाले कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबंधक महोदय के करकमलों से नकद पुरस्कार व प्रमाणपत्र प्रदान किये गये। इस अवसर पर अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा जी ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि राजभाषा के प्रचार-प्रसार में सभी ज्यादा से ज्यादा योगदान प्रदान करें ताकि भावनगर मंडल का नाम रोशन हो। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा जी ने उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने सांविधिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए ज्यादा से ज्यादा कार्य हिंदी में करने का आग्रह किया और विश्वास व्यक्त किया कि राजभाषा के प्रचार-प्रसार में सभी योगदान प्रदान करते रहेंगे। राजभाषा माह 2025 का सफल आयोजन अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमांशु शर्मा जी के बहुमूल्य मार्गदर्शन में श्री रामप्रीत मौर्य, मंडल बिजली इंजीनियर(टीआरडी) तथा राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अनुवादक श्री परेश. बी. मजीठिया तथा कनिष्ठ अनुवादक श्री नरपत सिंह, कार्यालय अधीक्षक श्री बी. एन. डाभी द्वारा संपन्न कराया गया। कार्यक्रम का सुचारू संचालन वरिष्ठ अनुवादक श्री परेश. बी. मजीठिया तथा धन्यवाद ज्ञापन श्री बी. एन. डाभी द्वारा किया गया।

रेलवे में तत्काल टिकट जारी करने हेतु सामान्य आरक्षण प्रणाली में आधार प्रमाणन की नई व्यवस्था

सामान्य यात्रियों को आरक्षण प्रणाली का अधिकतम लाभ पहुँचाने तथा टिकटों की दलाली एवं दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

भावनगर रेलवे मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 01 अक्टूबर 2025 से सामान्य आरक्षण खुलने के प्रथम 15 मिनटों के दौरान केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही IRCTC की वेबसाइट/ऐप के माध्यम से आरक्षित सामान्य टिकट बुक कर सकेंगे।

इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधान लागू रहेंगे –

- पीआरएस काउंटरों से टिकट बुकिंग की वर्तमान समय-सारणी यथावत रहेगी।
- पूर्व की भाँति, सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 10 मिनट तक अधिकृत टिकट एजेंटों को टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी।

पंजाब बाढ़: भगवंत मान ने अमित शाह से मांगा विशेष पैकेज, 20 लाख लोग प्रभावित

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर हाल ही में आई अभूतपूर्व बाढ़ के कारण राज्य में हुए भारी नुकसान के मद्देनजर विशेष पैकेज की मांग की। मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ से 2,300 से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं और 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा 3,200 स्कूल नष्ट हुए और 8,500 किलोमीटर सड़कें मलबे में बदल गई हैं।

भगवंत मान ने बताया कि अब तक बाढ़ के कारण 13,800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जो बढ़कर 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को स्थिति की गंभीरता से अवगत कराते हुए पंजाब के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की अपील की। अमित शाह ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और पंजाब को और अधिक सहायता देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने केंद्र पर आरोप लगाया कि राज्य पर अघोषित राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, क्योंकि राज्यपाल प्रधानमंत्री से मिलते हैं और मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि जबकि बिहार को चुनाव के मद्देनजर 7,000 करोड़ रुपये दिए गए, पंजाब में महिलाएँ और परिवार बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, और उनकी मदद के लिए अभी तक पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए।

इस दौरान भगवंत मान ने केंद्र से पंजाब के लिए विशेष पैकेज की मांग दोहराई और कहा कि राज्य हर संकट में देश के साथ खड़ा रहा है, अब जब संकट पंजाब पर आया है, तो केंद्र को भी राज्य के साथ खड़ा होना चाहिए।

देश का सबसे बड़ा बीमा फ्रॉड: विशाल सिंघल ने अपने परिवार को बनाकर बनाया करोड़ों का खेल

संभल और हापुड़ पुलिस ने एक चौंकाने वाला मामला सामने लाया है जिसमें मेरठ के 50 वर्षीय विशाल सिंघल पर अपने ही माता-पिता और पत्नी की हत्या कर करोड़ों रुपये की बीमा राशि हड़पने का आरोप है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह अब तक का देश का सबसे बड़ा बीमा फ्रॉड माना जा रहा है। विशाल सिंघल की करतूतों का खुलासा तब हुआ जब उसकी चौथी पत्नी श्रेया ने दो महीने पहले पुलिस से संपर्क किया और खुद की जान को खतरा बताते हुए इसे सीरियल किलिंग का मामला बताया।

श्रेय ने पुलिस को बताया कि विशाल ने 2017 में अपनी मां प्रभा देवी, 2022 में अपनी तीसरी पत्नी एकता और 2024 में पिता की हत्या की थी। इन घटनाओं को उसने हादसा दिखाकर बीमा क्लेम के रूप में करोड़ों रुपये हासिल किए। 2017 में मां की हत्या के बाद 25 लाख रुपये का बीमा क्लेम लिया गया। 2022 में तीसरी पत्नी की हत्या के बाद 80 लाख रुपये क्लेम किए गए, जबकि पिता की मौत के नाम पर कुल 50 करोड़ रुपये से अधिक के 64 पॉलिसियों का क्लेम हड़पने का मामला सामने आया।

पुलिस के अनुसार विशाल सिंघल का परिवार सामान्य आय वाला था, पिता फोटो स्टूडियो चलाते थे और विशाल बेरोजगार था। इसके बावजूद इतनी महंगी पॉलिसियों के प्रीमियम का भुगतान कैसे हुआ, यह एक बड़ा सवाल है। जांच में यह भी सामने आया कि पिता की मौत के तुरंत बाद विशाल ने लग्जरी वाहन खरीदे, जिससे उसकी नीयत पर शक और गहराया।

एएसपी अनुकृति शर्मा ने बताया कि गिरोह की कार्यप्रणाली बेहद संगठित थी। पहले पॉलिसी कराई जाती, प्रीमियम भरा जाता और फिर हत्या कर उसे हादसा दिखाया जाता। इसके बाद फर्जी दस्तावेज तैयार कर बीमा कंपनियों को गुमराह किया जाता और मोटी रकम का क्लेम पास कर लिया जाता। पुलिस के मुताबिक यह अपराध इंसानियत को शर्मसार करने वाला है और इसके पीछे विशाल का लंबे समय से सुसंगठित नेटवर्क काम कर रहा था।

विशाल सिंघल ने अब तक चार शादियां की हैं। चौथी पत्नी जीवित है और उसकी शिकायत से ही पूरा मामला उजागर हुआ। पुलिस को शक है कि पहली और दूसरी पत्नियों के मामले में भी उसकी संलिप्तता हो सकती है। इस गिरोह की जांच में अब तक 50 से अधिक आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है और 12 राज्यों में फैले इस नेटवर्क की गहन पड़ताल की जा रही है। कुल हड़पी गई बीमा राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।

संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि विशाल और उसके गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। इसके साथ ही उसकी अकूत संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी जांच में शामिल हो गया है और लखनऊ में केस दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी गई है। यह मामला बीमा कंपनियों और कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चेतावनी बन गया है, जिसमें बताया गया है कि लालच और पाप की हदें कितनी खतरनाक हो सकती हैं जब इंसानियत को ही तार-तार कर दिया जाए।

चिराग पासवान ने राजनीति का आधार जाति नहीं, बल्कि बिहारी पहचान बताया

लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मंगलवार को पटना में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि उनके लिए राजनीति का आधार जाति नहीं बल्कि बिहारियों की साझा पहचान है। उन्होंने कहा कि वह 14 करोड़ बिहारियों की बात करेंगे और उनकी राजनीति "बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट" की सोच पर आधारित होगी। पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता देने वाली राजनीति में विश्वास करती है।

चिराग ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी लगातार जातिगत समीकरणों की राजनीति करते हैं। उनके दिमाग में ईबीसी, ओबीसी, दलित और अन्य जातियां हो सकती हैं, जबकि उनके लिए बिहार की जनता केवल बिहारी है। उन्होंने 'एम-वाई' समीकरण का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ नेता इसका मतलब "मुस्लिम-यादव" समझते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के अनुसार इसका मतलब है "महिला और युवा"। यह नई सोच और नई पहचान है, जो बिहार की राजनीति में बदलाव की दिशा में काम करेगी।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि अब समय आ गया है कि महिलाओं और युवाओं की ताकत को बिहार की राजनीति के केंद्र में रखा जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकताओं में जनता की समस्याएं, राज्य का विकास और युवाओं के लिए रोजगार प्रमुख होंगे। इसके अलावा, उन्होंने जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर द्वारा बिहार सरकार के मंत्रियों पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की।

चिराग पासवान ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची जारी करना अपेक्षित था और रिपोर्ट आने के बाद इसके निष्कर्षों पर विचार किया जाएगा। उनके अनुसार, बिहार में लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सभी नागरिक राजनीतिक प्रक्रिया में समान रूप से शामिल होंगे और जातिगत राजनीति की जगह विकास और समान अवसरों की राजनीति को प्रोत्साहन मिलेगा।

सपा सांसद रामजीलाल सुमन हाउस अरेस्ट, आगरा में तनावपूर्ण हालात

आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के गिजौली गांव में हुए मारपीट प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद रामजीलाल सुमन और उनके समर्थकों के गांव जाने की घोषणा के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने हालात बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर सांसद को हाउस अरेस्ट कर लिया और उनके समर्थकों को बैरिकेडिंग के पीछे रोक दिया। इस दौरान रामजीलाल सुमन ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कड़े प्रबंधों के साथ उन्हें रोका।

सपा कार्यकर्ताओं ने सांसद को रोकने के बाद जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे अन्य सपा नेता और सांसद भी तनावपूर्ण माहौल को नियंत्रित करने में जुट गए। आगरा के डीसीपी पश्चिम जोन अतुल शर्मा ने बताया कि पुलिस ने सख्ती बरतते हुए कार्यकर्ताओं को नियंत्रित किया। सांसद के आवास पर एटा और इटावा के अन्य सांसद भी पहुंचे, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होने की आशंका बनी रही।

डीसीपी अतुल शर्मा ने चेतावनी दी कि गिजौली गांव में शांति व्यवस्था भंग करने की किसी भी कोशिश पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष पहले ही पंचायत स्तर पर समझौता कर चुके हैं और कानूनी रूप से भी संतुष्ट हैं। बावजूद इसके पुलिस ने स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया है।

इस घटना ने क्षेत्र में राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है और आगामी दिनों में प्रशासन और पुलिस की सतर्कता को और बढ़ा दिया है। हाउस अरेस्ट और बैरिकेडिंग के बावजूद सपा समर्थकों का विरोध और नारेबाजी जारी रही, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक गतिरोध के बावजूद स्थानीय प्रशासन को स्थिति पर कड़ी नजर रखनी होगी।

सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट बाढ़ पीड़ितों के लिए करेगा 10 करोड़ रुपए का योगदान

मुंबई। महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का हालात पैदा हो गया है। फसलों, खेतों और जीवनावश्यक वस्तुओं के नुकसान के कारण कई जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस आपदा की गंभीरता को देखते हुए श्रीसिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यास ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय की घोषणा न्यास के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री सदानंद सरवणकर, कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी और सभी ट्रस्टियों की मौजूदगी में की गई। श्रीसिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यास ने पहले भी विभिन्न आपदाओं और राष्ट्रीय संकटों के समय सहायता प्रदान की है। न्यास ने 2005 की भारी बारिश, 2008 के मुंबई आतंकी हमलों, 2013 के अकाल, 2014 की मालिन दुर्घटना, 2019 में चिपलुन के टिवरे गांव में बांध टूटने की घटना और पुलवामा आतंकी हमलों में शहीदों के परिवारों को आर्थिक मदद दी थी। इस तरह न्यास ने हमेशा समय पर राहत पहुँचाने और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का उदाहरण पेश किया है। इस बार भी न्यास का यह कदम बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत और मनोबल बढ़ाने में मददगार साबित होगा। न्यास के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी ने राज्य की अन्य संस्थाओं और संगठनों से अपील की है कि वे भी मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान दें और बाढ़ पीड़ितों की मदद में हाथ बटाएँ।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कदम न केवल आपदा में फंसे लोगों को तत्काल राहत प्रदान करते हैं, बल्कि समाज में मानवीय सहयोग और सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा देते हैं। ऐसे प्रयासों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की गति तेज होती है और जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिलती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा संघर्ष समाप्ति योजना का किया स्वागत, सभी पक्षों से एकजुटता की अपील

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा संघर्ष को समाप्त कराने वाली योजना का खुले तौर पर स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल फलस्तीन और इजराइल के लोगों के लिए, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक शांति, सुरक्षा और विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि "सभी संबंधित पक्ष" इस योजना का समर्थन करेंगे और संघर्ष समाप्ति की दिशा में एकजुट होंगे।

ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई वार्ता के बाद यह योजना पेश की गई। इसमें गाजा में युद्ध तत्काल रोकने, हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों की रिहाई और गाजा के असैन्यीकरण के उपाय शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर लिखा कि हम गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की व्यापक योजना का स्वागत करते हैं। उन्होंने इसे क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया।

हालांकि, हमास ने अब तक इस योजना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं, आठ मुस्लिम बहुल देशों और फलस्तीनी प्राधिकरण ने इस योजना का स्वागत किया है। यह शांति प्रयास 7 अक्टूबर, 2023 को इजराइली शहरों पर हमास द्वारा किए गए हमले और लगभग 1,200 लोगों की हत्या के बाद शुरू हुए इजराइली जवाबी हमलों की पृष्ठभूमि में आया है। उस समय हमास ने 251 लोगों को बंधक बनाया था, जिनमें से 50 से अधिक अभी भी उसकी गिरफ्त में हैं।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजराइली हमलों में अब तक 66,000 से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और भोजन व दवाओं की गंभीर कमी के कारण यहाँ एक बड़े मानवीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले महीने चेतावनी दी थी कि गाजा में कुपोषण की दर "खतरनाक स्तर" तक पहुँच गई है। ट्रंप की शांति योजना को चीन और कई यूरोपीय देशों ने भी सराहा है। योजना की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद, ट्रंप ने कहा कि वह हमास को इस योजना पर प्रतिक्रिया देने के लिए तीन से चार दिन का समय देंगे, ताकि सभी पक्ष इसे गंभीरता से विचार कर सकें और जल्द से जल्द संघर्ष समाप्ति की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकें।

जबलपुर: सिहोरा में दुर्गा पूजा पंडाल में घुसी तेज रफ्तार बस, 18 से अधिक घायल

जबलपुर। मध्य प्रदेश के सिहोरा इलाके में मंगलवार रात एक भयावह हादसा हुआ, जब एक तेज रफ्तार यात्री बस पंडाल में घुस गई। यह दुर्गा पूजा पंडाल उस समय भरे हुए श्रद्धालुओं से भरपूर था, जिससे दुर्घटना की गंभीरता और बढ़ गई। बस के पंडाल में घुसते ही वहां भगदड़ मच गई और कम से कम 18 लोग घायल हो गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे पंडाल की ओर बढ़ी। लोग दौड़ते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल लोगों में कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद बड़े अस्पताल में रेफर किया गया।

स्थानीय प्रशासन ने मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया और दुर्घटना की वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, चालक की लापरवाही या ब्रेक फेल होने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। हादसे के बाद पंडाल में पहुंचे आयोजकों ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। यह घटना दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक उत्सवों के दौरान भीड़ प्रबंधन और यातायात नियंत्रण की अहमियत को उजागर करती है।

स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आगामी त्योहारों और पंडाल आयोजनों में सुरक्षा उपायों को और कड़ा किया जाएगा ताकि ऐसी घटनाएं फिर से न हों। पुलिस और प्रशासन ने आसपास के इलाकों में यात्रा और पार्किंग के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। इस दुखद हादसे ने स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में डर और चिंता बढ़ा दी है। घटना की छानबीन जारी है और सभी घायलों के सुरक्षित स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की जा रही है।

लखनऊ : जेल में सपा के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमला, KGMU में इलाज

लखनऊ। गोसाईंगंज जिला जेल में मंगलवार देर शाम समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर एक बंदी ने रॉड से हमला कर दिया। हमले में उनके सिर में गंभीर चोट आई, जिसके चलते उन्हें जेल अस्पताल में प्राथमिक इलाज देने के बाद कीमती पांच टांके लगे। चोट की गंभीरता को देखते हुए उन्हें केजीएमयू (किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी) रेफर किया गया। जांच में सामने आया कि घटना की वजह एक मामूली विवाद था। जेल में सफाई का काम करने वाले बंदी विश्वास को पानी देने के लिए बुलाया गया था। विश्वास देर से पहुंचा, जिस पर पूर्व मंत्री ने उसे अमर्यादित टिप्पणी की। नाराज बंदी ने पास में रखी आलमारी की रॉड उठाकर पूर्व मंत्री पर हमला कर दिया।

हमला इतना अचानक और तेज था कि गायत्री प्रजापति फर्श पर गिर गए और उनके सिर से खून बहने लगा। मौके पर मौजूद अन्य बंदियों और जेल कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और विश्वास को पकड़ लिया।

गायत्री प्रजापति ने बताया कि हमला करने वाला बंदी शातिर और हठी था। जेल प्रशासन के अनुसार, पूर्व मंत्री कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, जैसे डायबिटीज, बीपी, गुर्दा की समस्या और कमर दर्द, और उन्हें लंबे समय से जेल अस्पताल में रखा गया था। इस दौरान उनकी देखरेख में कोई लापरवाही नहीं होने दी गई।

घटना के तुरंत बाद वरिष्ठ जेल अधीक्षक आरके जायसवाल ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और पूर्व मंत्री खतरे से बाहर हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बंदी के साथ कड़ी पूछताछ शुरू कर दी गई है और पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है।

केजीएमयू में भर्ती होने के बाद गायत्री प्रजापति का मेडिकल परीक्षण किया गया। डॉक्टरों ने कहा कि सिर पर लगी चोट के बावजूद पूर्व मंत्री की हालत स्थिर है। जेल प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह के किसी भी विवाद को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे।

उत्तराखंड में आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी: पारिवारिक कलह और प्रेम संबंधों से तनाव मुख्य कारण

हल्द्वानी। उत्तराखंड में आत्महत्या के मामलों में लगातार बढ़ोतरी ने राज्य और समाज दोनों में चिंता बढ़ा दी है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में आत्मघाती घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके पीछे पारिवारिक कलह, आर्थिक तंगी, शिक्षा और रोजगार से जुड़े दबाव, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और युवाओं में प्रेम संबंधों के तनाव जैसे कारण प्रमुख हैं।

विशेष रूप से पारिवारिक कारणों से परेशान होकर वर्ष 2023 में 171 लोगों ने अपनी जान दे दी। वहीं, युवाओं में प्रेम संबंधों के तनाव से उत्पन्न मामलों में 137 लोगों ने आत्मघाती कदम उठाया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2023 में उत्तराखंड में आत्महत्या के मामले 2022 की तुलना में 15.5 प्रतिशत बढ़ गए। जहां वर्ष 2022 में 814 लोगों ने अपनी जान दी थी, वहीं 2023 में यह संख्या बढ़कर 940 हो गई। रिपोर्ट में लिंग और कारणों के आधार पर भी आंकड़े जारी किए गए हैं। वर्ष 2023 में 57 पुरुष और 25 महिलाओं ने आत्महत्या की। आर्थिक नुकसान होने पर 23 लोगों ने, शादी के बाद समस्याओं के चलते 91 लोगों ने, परीक्षा में फेल होने के कारण 19 लोगों ने, विवाहेत्तर संबंधों को लेकर 33 लोगों ने और दहेज के झगड़े में 15 लोगों ने अपनी जान दे दी।

विशेषज्ञों का मानना है कि आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के पीछे सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की उपेक्षा सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं और परिवारों को समय पर मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना, तनाव प्रबंधन की शिक्षा देना और समाज में जागरूकता फैलाना आवश्यक है। इसके साथ ही सरकार को भी आत्महत्या रोकथाम के लिए प्रभावी नीतियां बनानी और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा।

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि राज्य में आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और पारिवारिक ढांचे पर भी गंभीर प्रभाव डालती है। उन्होंने सुझाव दिया कि समस्या की जड़ तक पहुँचने के लिए परिवार, समाज और प्रशासन को एक साथ मिलकर काम करना होगा। मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता, तनाव प्रबंधन और समय पर हस्तक्षेप के माध्यम से ही उत्तराखंड में इस बढ़ती समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है और परिवारों को अकल्पनीय दुख से बचाया जा सकता है।

किसान मशरूम की खेती से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहे हैं : राज्य सरकार की नई योजना

राज्य सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में मशरूम की खेती को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने कृषि विभाग के तहत 2025-26 के लिए मशरूम अवयवों (मशरूम किट और मशरूम हट) की योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को जल्द आवेदन करना होगा, क्योंकि यह "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर दिया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत मशरूम उत्पादन के लिए पैडी/ओयेस्टर, बटन मशरूम किट, बकेट मशरूम किट और झोपड़ी निर्माण पर अनुदान प्रदान किया जा रहा है। पैडी/ओयेस्टर मशरूम किट की इकाई लागत 75 रुपये है, जिस पर किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान अर्थात् प्रति किट 67.50 रुपये का लाभ मिलेगा। वहीं बटन मशरूम किट की इकाई लागत 90 रुपये है और इसमें भी किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान अर्थात् 81 रुपये प्रति किट मिलेगा। इस घटक के अंतर्गत प्रत्येक कृषक न्यूनतम 25 किट और अधिकतम 100 किट का लाभ ले सकता है। बकेट मशरूम किट के लिए इकाई लागत 300 रुपये है, जिस पर 90 प्रतिशत अनुदान अर्थात् 270 रुपये प्रति किट दिया जाएगा। इस घटक के अंतर्गत प्रति कृषक न्यूनतम 2 किट और अधिकतम 10 किट का लाभ मिलेगा। ध्यान रहे कि पैडी/ओयेस्टर या बटन मशरूम किट के लाभार्थी भी इस घटक का लाभ ले सकते हैं।

इसके अलावा, मशरूम उत्पादन के लिए झोपड़ी निर्माण के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है। झोपड़ी की इकाई लागत 1,79,500 रुपये है, जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान अर्थात् 89,750 रुपये प्रति झोपड़ी मिलेगा। योजना के अनुसार, झोपड़ी का निर्माण 1,500 वर्गफीट में किया जाएगा और प्रत्येक कृषक को अधिकतम एक झोपड़ी का लाभ मिलेगा।